International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 3, Issue 12, pp: 644-651 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

# भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के प्रदर्शन पर एक अध्ययन

**Dr. Ajay Swarup Saxena**
*(Associate Professor)*
*Department of Commerce*
*D.A-V College Kanpur U.P.*

Date of Submission: 26-11-2021 Date of Acceptance: 12-12-2021

**सार**

स्वतंत्रता के बाद से सरकारों ने लगातार भारत में वित्तीय संकट में सुधार और गरीबी को कम करने पर जोर दिया है। 1950 के दशक में ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का निर्माण किया जो की भारत के 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों पर गरीबों के लिए वित्तीय संकट में सुधार करने का एक प्रयास था। इसके बाद वित्तीय संकट को काम करने के उद्देश्य से और उपाय भी किए गए। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण और ग्रामीण बैंकिंग का विस्तार करने के लिए 1960 के दशक के अंत में तथा 1970 और 1980 के दशक के दौरान एक आक्रामक अभियान चलाया गया। भारत की अर्थव्यवस्था शुरुआत से ही कृषि आधारित है और देश की राष्ट्रीय आय में प्रमुख योगदानकर्ता है। लेकिन भारत का अधिकांश क्षेत्र कमजोर वर्ग है या गरीबी की रेखा के नीचे से आता है। अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद बड़ी पहल की और देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्न बढ़ाने और खेती के संचालन को बढ़ावा देने के साथ, भारत के वंचित वर्ग की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किया जैसे स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति योजना आदि लेकिन फिर भी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के क्रांतिकारी विकास लिए और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और प्रचार की आवश्यकता महसूस की गई।

(सूक्ष्म-वित्त) माइक्रोफाइनेंस की सुविधा अकसर उन्हीं लोगों को दी जाती है जोकि एक तरफ कम आय वर्ग वाले होते हैं और उनके इलाके में बैंक की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होती है साथ ही स्व-रोजगार हेतु ऋण के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर होते है। माइक्रोफाइनेंस की सुविधा वर्तमान में बैंक-रहित क्षेत्रों में प्रमुख वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं के विस्तार के रूप में एक बेहतर विकल्प साबित हुआ है. साथ ही विभिन्न उधारदाताओं द्वारा जोकि ऋण देने में अपनी मनमानी करते थे, अब समाज के विविध वर्गों को सुविधाएं देने में रूचि रखने लगे हैं. साथ ही क़ानून के प्रावधानों के अधीन भी हो गए है।

इस लेख को लिखने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र का तुलनात्मक विकास और भारत में सूक्ष्म वित्त सेवाओं के विकास का विश्लेषण करना है।

## I. परिचय

भारत में भी माइक्रोफाइनेंस भारत की अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय जरूरतें अस्थिर, अनिश्चित, और अनियमित हैं। उनकी पूर्वापेक्षाओं की आलोचनात्मक जांच से पता चलता है कि गरीब लोग वित्तीय सेवाओं को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि वे विश्वसनीय सुविधाजनक और लचीले हों। भारत में माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने वाले कई संस्थाये है जिसमें औपचारिक वित्तीय संस्थान और

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 3, Issue 12, pp: 644-651 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

दूसरे निजी साहूकार शामिल हैं। माइक्रोफाइनेंस सेवाएं बैंकों, यूनियनों और माइक्रोफाइनेंस संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं जिन्हें माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (एमडीओ) के रूप में भी जाना जाता है। माइक्रोफाइनेंस अब स्पष्ट रूप से एक विश्वव्यापी आंदोलन है जिसे सरकारी निगमों, बैंकों, विकास एजेंसियों, व्यापारिक समुदायों, नागरिक, और समाजों द्वारा अपनाया गया जाता है।

भारत में आर्थिक विकास की वृद्धि और बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के कारण वित्तीय सहायता की मांग बढ़ रही है। विशेष रूप से सूक्ष्म वित्त में, यह मांग सिर्फ निगमों और आर्थिक रूप से मजबूत समूहों की ही नहीं बल्कि समाज के निचले तबके की भी है। समाज के निचले वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। देश में अधिकांश वाणिज्यिक बैंक लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन फिर भी वित्तीय सुरक्षा के अभाव में समाज का गरीब वर्ग वित्तीय सहायता से वंचित है। इस वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) की स्थापना की गई जो समाज के वंचित वर्ग के लिए एक प्रदाता के रूप में काम करते थे। 12 जुलाई 2002 को अपराह्न अटल बिहारी वाजपेयी ने 10वीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर धकेलने के लिए आठ सूत्री एजेंडा की रूपरेखा तैयार की, जिसे गरीबी पर हमला करने के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाया जा रहा है। दुनिया भर में सूक्ष्म वित्त की वृद्धि कई पहलुओं में दिखाई दे रही है। नाबार्ड, एसएचजी बैंक, लिंकेज कार्यक्रम में 800 एनजीओ किसी न किसी रूप में वित्तीय इंटरमीडिएशन में शामिल हैं। इसके अलावा 350 नई पीढ़ी की सहकारी समितियां भी हैं जो बचत और ऋण सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत में सामाजिक और वित्तीय मध्यस्थता की भूमिका के साथ ही सामुदायिक संस्थानों का भी विकास हुआ हैं।

पिछले कुछ दशकों में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र तेजी से बढ़ा है और वर्तमान में इनके पास भारत की गरीब आबादी के लगभग 102 मिलियन खाते (बैंकों और छोटे वित्त बैंकों सहित) हैं

आर्थिक अवसर फैलाने और गरीबी के खिलाफ लड़ने में वित्त एक असाधारण प्रभावी उपकरण है। वित्त तक पहुंच गरीबों को अपनी समृद्ध प्रतिभा का उपयोग करने के साथ और अधिक अवसरों के लिए रास्ते खोलने की अनुमति देता है, और सतत ऋण सेवाएं प्रदान करना इनमें से एक है जिसका मतलब गरीबों की आय और उत्पादकता में वृद्धि करना।

1980 के दशक में अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चला है कि बहुत बड़ी संख्या में गरीब से गरीब व्यक्ति औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की पहुंच से बाहर बना हुआ है। लेकिन यह महसूस किया जा सकता है कि मौजूदा बैंकिंग नीतियां प्रक्रिया और प्रणाली गरीबों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। और इस स्थिति में सूक्ष्म वित्त समाधान के रूप में है। हालांकि भारत में बैंकिंग प्रणाली में असाधारण और अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है।

**ग्रामीण मॉडल बैंक:**

इस मॉडल को वर्ष 1970 के दशक में एक बांग्लादेशी नोबेल विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस द्वारा प्रतिपादित किया गया।

इस मॉडल ने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Bank) के निर्माण को प्रेरित किया है। इस प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है।

माइक्रोफाइनेंस आज भारत में वित्तीय समावेशन और विकास लाने में गरीबी को कम करने के लिए एक समाधान का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में माइक्रोफाइनेंस आर्थिक उपकरण है माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई) बैंकों और गरीबों के बीच एक सेतु के रूप में सामने आए जिनके ऋण का एकमात्र

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 3, Issue 12, pp: 644-651 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

स्रोत अब तक साहूकार रहा है। सूक्ष्म-वित्त)माइक्रोफाइनेंस की मुख्य विशेषताएं हैं:

• इसके अन्दर दिए जाने वाले ऋण छोटी राशि के होते हैं, जैसे-सूक्ष्म ऋण
• ऋण देने का मूल उद्देश्य आम तौर पर आय सृजन से जुड़ा होता है.
• कम आय-वर्ग के लोगो को इस तरह का ऋण प्रदान किया जाता है.
• लघु अवधि के ऋण होते हैं
• उच्च स्तर पर इनकी पुनः चुकौती होती है
• बिना किसी सामानांतर व्यवस्था के इसमें ऋण प्रदान किया जाता है.

**अनुसंधान पद्धति**

हमारी इस शोध पद्धति मे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवाओं के बीच तुलना करने का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस शोध में हम प्राथमिक डेटा के साथ-साथ सेकेंड्री डेटा का भी उपयोग करेंगे। प्राथमिक डेटा प्रश्नावली और केंद्रित समूह साक्षात्कार द्वारा एकत्र किया गया है और माध्यमिक डेटा संदर्भ पुस्तकों पत्रिकाओं और इंटरनेट द्वारा एकत्र किया गया है।

**भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की अवधारणा**

भारत में माइक्रोफाइनेंस की जड़ें 1970 के दशक की शुरुआत में गुजरात में पाई गईं जब स्व-रोजगार महिला संघ ने असंगठित क्षेत्र की गरीब महिलाओं को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समूह का गठन किया। इस अवधारणा को स्वयं सहायता समूह एसएचजी कहा जाता है। स्वयं सहायता समूह और बैंकिंग क्षेत्र को जोड़ने वाला कार्यक्रम भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तहत 1989 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम से जुड़े बैंक समूह के क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण में सहायता करते हैं।

2014 में स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या 74.30 लाख थी (नाबार्ड 2014) और वर्ष 2021 तक इसमें 7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमानित अनुमान है। भारत में ऐसे समूहों की वृद्धि दर समय के साथ धीमी हुई है। इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण यह है कि अधिकांश स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच एकरूपता और समूह में एकता की कमी (तिवारी और अरोड़ा 2015) है। माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को देश में स्वयं सहायता समूह की तुलना में, बाद में पेश किया गया था। हालांकि पूर्व की वृद्धि और कुल कारोबार बाद वाले की तुलना में अधिक रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं जैसे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) बैंक और जन धन योजना ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के विकास में सहायता की है। ये दोनों समाज के एक ही गरीब तबके को निशाना बनाते हैं। माइक्रोफाइनेंस उद्योग की वृद्धि 28 प्रतिशत से अधिक है। वित्त वर्ष 2019 में इसके ऋण पोर्टफोलियो में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (2018) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र के वर्ष 2017 से 2021 तक सालाना 28 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ने की उम्मीद है।

वित्तीय समावेशन में वर्तमान केंद्र सरकार की बढ़ती भागीदारी देश के वंचित लोगों को प्रदान किए गए वित्तीय लाभों के कारण भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का समय के साथ विस्तार हो रहा है।

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 3, Issue 12, pp: 644-651 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

## II. बाजार का आकार और विकास

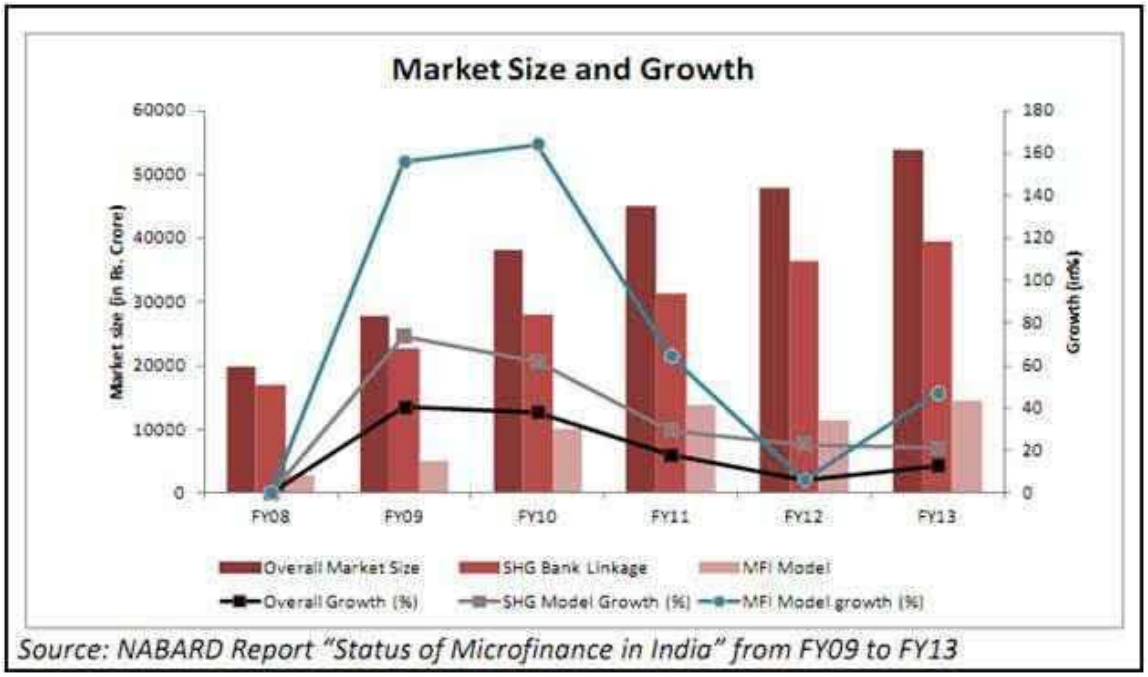


*Source: NABARD Report "Status of Microfinance in India" from FY09 to FY13*

**भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्थान**

माइक्रोफाइनेंस संस्थान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं लाभ के लिए और लाभ के लिए नहीं। दूसरी श्रेणी के संस्थान आमतौर पर ट्रस्ट और सोसाइटी होते हैं जो अनुदान की मदद से संचालित होते हैं। ये संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत होते है दूसरी ओर सहकारी समितियां या गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनी हैं जो सामान्यता लाभ के लिए कार्य करते है। हाल की अवधि में कई छोटे वित्तीय संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक, (आरबीआई ) से लाइसेंस प्राप्त करके गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में बदल रहे हैं।

माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एमएफआई) को पंजीकृत करने के मूल रूप से दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि कंपनी बनाई जाए और फिर मंजूरी के लिए आरबीआई के पास आवेदन किया जाए। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं 5 करोड़ शुद्ध स्वामित्व वाले फंड और प्रमोटरों की मजबूत प्रोफाइल होनी चाइये। दूसरा तरीका सेक्शन 8 में कंपनी (पहले सेक्शन 25 कंपनी) को पंजीकृत करना और केंद्र सरकार के लाइसेंस के लिए आवेदन करना है जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

अधिकतम 50000 रुपये व्यावसायिक उद्देश्य के लिए और 125000 रुपये आवासीय आवास के लिए दिए जा सकते हैं। कोई न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता नहीं है। आप खुद फैसला करें, आरबीआई के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरबीआई ने इस कंपनी को पंजीकरण के साथ कुछ अन्य शर्तों में छूट दी है।

कंपनी को धारा 8 के तहत जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कंपनी को अपने स्वयं के फंड का निवेश करना होगा और आपका माइक्रो फाइनेंस व्यवसाय शुरू करना होगा। इसके अलावा कंपनी दान के माध्यम से भी धन जुटा सकती है। यहां तक कि अगर आप एक एनबीएफसी कंपनी को पंजीकृत करने की योजना बना रहे हैं और व्यवसाय में 5 करोड़ रुपये निवेश करने के इच्छुक हैं तो भी जमा लेने की अनुमति नहीं है। आरबीआई की प्रक्रिया के अनुसार पहले

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 3, Issue 12, pp: 644-651 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

आपको एक एनबीएफसी गैर जमा स्वीकार करने वाली कंपनी को पंजीकृत करना होगा और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से जमा लेने की स्थिति के लिए आवेदन करना होगा। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि यदि आप अपनी एनबीएफसी को पंजीकृत करने की योजना बना रहे हैं तो पहले सेक्शन 8 कंपनी से शुरुआत करें अपने कौशल का परीक्षण करें और फिर आगे बढ़ें। साथ ही कंपनी के पहले से मौजूद संस्था के निष्क्रिय लाइसेंस को भी खरीद सकती हैं।

सूक्ष्म वित्त कंपनियों के तहत ऋण बहुत जटिल नहीं हैं। अधिकतर असुरक्षित ऋण प्रदान किए जाते हैं और मासिक भुगतान या साप्ताहिक पुनर्भुगतान के विरुद्ध होते हैं। ब्याज ज्यादातर 20 प्रतिशत से 26 प्रतिशत की सीमा में लिया जाता है। इसके अलावा निम्नलिखित बिंदु भी महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रकार हैं:

एनबीएफसी अपने ग्राहकों से अलग-अलग ब्याज दर वसूल सकती है लेकिन भिन्नता 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष राशि घटाने के तरीके पर लिया जाने वाला ऋण पर ब्याज। सूक्ष्म वित्त कंपनियां सभी कार्यालयों या साहित्य में प्रभावी ब्याज दर प्रदर्शित करेंगी। कंपनियों को प्रत्येक सदस्य को ब्याज दर अन्य सभी नियमों और शर्तों को बताते हुए एक ऋण कार्ड जारी करना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और अन्य लिंक कार्यक्रमों में भी ऋण दिए जाते हैं। यदि 90 दिनों के भीतर कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा हालांकि प्रावधान मानदंड धारा 8 कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

रिजर्व बैंक की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष बैंकों के साथ पंजीकृत केवल 69 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और माइक्रोफाइनेंस संस्थान थे। हालाँकि उनमें से अधिकांश कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर (aaaआई आर ऐ 2018) के थे। दूसरी ओर शेष बैंक गैर-लाइसेंस प्राप्त छोटे पैमाने के सूक्ष्म वित्त संस्थान थे। भारत में कुछ सबसे बड़े और सबसे संगठित छोटे पैमाने के वित्तीय संस्थानों में एसकेएस, बंधन, उज्जीवन, जनलक्ष्मी, बेसिक्स, स्पंदना, और साटन शामिल हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में वर्तमान में ऐसे संस्थानों के साथ-साथ उधारकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक है।

**माइक्रोफाइनेंस और स्व-सहायता समूह (एसएचजी)**

माइक्रोफाइनेंस दो बुनियादी मॉडल के तहत चल रहे हैं **पहला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) मॉडल है** ये एसएचजी मॉडल बैंकों द्वारा सीधे वित्तपोषण के सिद्धांत पर काम करता है। एक तरफ से यह स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) है जो समूहों एसजी की बचत पर आधारित है जो स्वयं प्रबंधित समुदाय आधारित समूह है जो अपने सदस्यों को बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। एसएचजी 15 से 25 स्व-चयनित व्यक्तियों से बने होते हैं जो नियमित रूप से आमतौर पर साप्ताहिक या पाक्षिक बचत के लिए मिलते हैं और यदि वांछित हो तो समूह द्वारा निर्धारित दर पर मासिक ब्याज का भुगतान करते हुए छोटी अवधि के लिए उधार लेते हैं। सरकार भी इन स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए आगे आ रही है। भारत में वित्तीय संस्थानों और एसएचजी ने दशकों से गरीबी कम करने के लिए अपना मानक निर्धारित किया है।

**दूसरी ओर सूक्ष्म वित्त संस्थान मॉडल है** जैसे- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड जो वंचितों का पता लगाते हैं और उन्हें अपने स्वयं के और सरकारी संगठनों से विशेष रूप से सिडबी से वित्त प्राप्त करने में मदद करते हैं। माइक्रो वित्तीय संस्थान माइक्रोफाइनेंस भारत मे गरीबी उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी सफलता के लिए व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की श्रम शक्ति कृषि 60 प्रतिशत उद्योग 12 प्रतिशतऔर सेवाओं 28 प्रतिशत से बनी है जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 3, Issue 12, pp: 644-651 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

कि आज भी कृषि आय और रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ आई । संस्थान को कृषि और आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति योजना और संचालन से संबंधित सभी मामलों से मान्यता प्राप्त थी इसके अलावा कृषि गांव के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने और विनियमन करने के लिए सभी आवश्यक मामलो मे भी मान्यता प्राप्त थी।

नाबार्ड का कॉर्पोरेट मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और वंचित वर्ग के लिए माइक्रोफाइनेंस उपलब्ध कराना है। यह औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से छूटे हुए गरीबों तक पहुंचने का एक साधन प्रदान करता है। नाबार्ड अनिवार्य रूप से एक स्केलेबल और टिकाऊ रोजगार पैदा करने और कृषि से संबंधित व्यवसाय के लिए धन की अनुपलब्ध उपलब्धता को पूरा करने का नया तरीका है। इसने पिछले तीन दशकों से स्वयं सहायता समूहों को लिंकेज प्रदान किया है। नाबार्ड ने स्वयं को एक सूत्रधार और पहल के संरक्षक की भूमिका सौंपी थी। कार्यक्रम (नाबार्ड 2012) में भाग लेने वाले सभी बैंकों को 100 प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हितधारकों के बीच क्षमता निर्माण एक साझा मंच पर विभिन्न हितधारकों को लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अलावा नाबार्ड सभी हितधारकों के बीच सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़ी संख्या में सेमिनार कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

कुछ वित्तीय संस्थान ऐसे भी हैं जो अस्तित्व में आए लेकिन चल नहीं पाए फिर भी उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन संस्थानों ने लोगों को सूक्ष्म वित्त का विस्तार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ जोड़ा है।

भारत में उल्लेखनीय औपचारिक क्षेत्र के माइक्रोफाइनेंस प्रदाता सिडबी भारत में लघु उद्योग विकास बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक आदि हैं। कई प्रयासों के बावजूद अनौपचारिक क्षेत्र जिसमें जमींदार और व्यापारी शामिल हैं उच्च दरों पर माइक्रोफाइनेंस सुविधा प्रदान करते हैं। 2003 में आर एफ ऐ एस के द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अभी भी अनौपचारिक एजेंटों से पैसे उधार लेते हैं।

**भारत में माइक्रो फाइनेंसिंग के मुद्दे**

भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को बड़ी संख्या में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी सफलता में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। इन वित्तीय संस्थानों के कामकाज में कुछ नुकसान हैं जैसे उच्च ब्याज दरें अवसरवाद ग्राहकों को पेश किए जाने वाले उत्पादों में कोई विविधता नहीं और ऐसी कई अन्य चुनौतियों शामिल हैं। शहरी गरीबों को इसकी पहुंच में शामिल नहीं करना उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए खराब क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली जागरूकता की कमी खराब ऋण प्रबंधन और कमजोर ऋण संग्रह प्रणाली। नुकसान के बावजूद लोगों को आसान ऋण देना कामकाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

एमएफआई जमाकर्ताओं की जमाराशियां बहुत विषम हैं। ग्राहकों को विभाजित करना और प्रत्येक समूह के लिए विशिष्ट रणनीति विकसित करना उनके कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उनके ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा है इसके अतिरिक्त ग्राहकों को जमा आकार और उम्र और लिंग जैसे मानदंडों के आधार पर विभाजित करना भी है।

एमएफआई के लिए यह उपयोगी होगा कि वे अपने स्वयं के क्लाइंट डेटाबेस का अधिक गहराई से विश्लेषण करें ताकि मार्केटिंग और क्रॉस सेलिंग प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से उन्मुख किया जा

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 3, Issue 12, pp: 644-651 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

सके अधिकांश एमएफआई ने अभी तक ऐसा नहीं किया है और इस काम के महत्व को नहीं पहचाना है। यद्यपि कुल ऋण खातों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, किंतु ग्राहकों के गरीबी-स्तर पर इन ऋणों का वास्तविक प्रभाव से संबंधित कुछ स्पष्ट तथ्य मौजूद नहीं है, क्योंकि ग्राहकों के सापेक्ष गरीबी-स्तर में सुधार से संबंधित सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का डेटा पूर्णतः खंडित है।

बैंक और अन्य एमएफआई आमतौर पर बचत को आकर्षित करने में प्रमुख प्रतिस्पर्धा का गठन करते हैं। जमा पर कब्जा करने में एमएफआई की मुख्य ताकत उनकी अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दरें व्यक्तिगत और कुशल सेवा वित्तीय दृढ़ता की एक छवि है कोई कमीशन या खाता रखरखाव शुल्क नहीं लिया जाता है खाता खोलने के लिए कम न्यूनतम राशि और स्थानीय जड़ें क्षेत्रीय रूप से शामिल हैं।

जमाराशियों को जुटाने में एमएफआई की कमजोरियों में शामिल हैं, बैंकों के समान राष्ट्रीय नेटवर्क की कमी जो भुगतान और स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करते है। उनकी अपेक्षाकृत कम नेटवर्क और संपत्ति स्वचालित टेलर मशीनों( एटीएम) की कमी सेवाओं की सीमित रेंज तरलता, जोखिम, टर्म मिसमैच जोखिम, ब्याज दर जोखिम, और विनिमय दर जोखिम, इन जोखिमों से एमएफआई पर जमा संग्रहण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विपणन गतिविधियों के द्वारा जमा को आकर्षित करना एमएफआई के लिए नई चुनौतियां पैदा करता है। एमएफआई को सभी स्थापित मध्यस्थों के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। विज्ञापन अभियानों की योजना बनाने ग्राहकों और ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर का विश्लेषण करने और संचार के उपयोग की योजना बनाने और निर्देशित करने के लिए एक विपणन विभाग या इकाई आवश्यक होनी चाइये।

**निष्कर्ष**

अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म वित्त के सकारात्मक विकास को दर्शाता है। माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से आर्थिक विकास का मानव पूंजी के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और ये गरीबी की आवृत्ति और विशेषाधिकार प्राप्त सशक्तिकरण को प्रभावित करता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि माइक्रोफाइनेंस भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नाबार्ड और सिडबी जैसे संस्थानों ने गरीब लोगों और समाज के प्रत्येक विंग के उत्थान के लिए माइक्रोफाइनेंस के भविष्य के संचालन को मजबूत और मुख्य धारा के साथ समन्वय प्रयास करने का आह्वान किया है। नाबार्ड और सिडबी ने माइक्रोफाइनेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किया है। गरीबों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की राशि निर्धारित की जा रही है। बैंकिंग नेटवर्क पूरी दुनिया में विस्तार चरण से गुजरा और महत्वपूर्ण बात यह है कि माइक्रोफाइनेंस से वंचित लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं का लाभ मिला। नाबार्ड और सिडबी जैसे संस्थान भारत में सूक्ष्म वित्त की दुनिया में मील का पत्थर साबित हुए हैं।

गरीबी से नीचे के लोगों के उत्थान में सूक्ष्म वित्त का योगदान को भुलाया नही जा सकता है लेकिन सत्य यह भी है कि इसमे अभी और सुधार और कार्य करने की जरुरत है। इसलिए 2022 तक हम मानते हैं कि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के पास वंचित लोगों के लिए वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनने के लिए कम कमियां होंगी और यह विकास में और अधिक योगदान देगा जिससे अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म वित्त की विकास दर के प्रक्षेपण में मदद मिलेगी।

**इस लेख में द हिन्दू, देनिक जागरण, देनिक भास्कर, उमर उजाला, द इंडियन एक्सप्रेस, बिज़नस लाइन, आदि में प्रकाशित इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट के लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में अथर्व्यवस्था और भारत में सूक्ष्म वित्त के पुनरुद्धार व उससे संबंधित भिन्न-भिन्न पहलुओं पर चर्चा की**

**गई है। आवश्यकतानुसार कुछ अर्थशास्त्रियों के विचार के इनपुट को भी शामिल किया गया है।**

## References

[1]. Michael Tucker and Gerard Miles "Financial performance of Microfinance Institutions - A comparison of performance of Regional Commercial banks by geographic regions" Journal of Microfinance Vol. 6 No.1 2003.
[2]. Sachs JD (2005) the end of poverty Allen Lane New Delhi
[3]. Murdoch and Rutherford (2003) as cited in Basu (2006).
[4]. Abdul Qayyum and Ahmad M "Efficiency and sustainability of microfinance institution in South Asian" Pakistan Institute of Development Economics 2006.
[5]. SenMitali "Assessing social performance of MFIs in India" ICFAI Journal of Applied finance Vol. 14 No: 86 2008 pp. 77-86.
[6]. Pankaj.K.Agarwal and S.K.Sinha "Financial performance of microfinance institutions of India: A cross sectional study" Delhi Business Review Vol.11 No.2 July- Dec 2010.
[7]. In a study conducted by Kaur and Gandhi (2006) they explore the issue of women empowerment in Jalandhar Punjab.
[8]. Zohra Bi AjitaPoudelJunaidSaraf "Performance and Sustainability of MFIs in India" Tenth AIMS International Conference on Management January 6 – 9 2013.
[9]. Microfinance Institution Networks. (2015) Annual Report of Microfinance Institution Network Gurgaon Retrieved from http://mfinindia.org/wp-content/uploads/2015/08/MFIN_Annual Report -2015.pdf
[10]. Prakash Singh "Performance analysis of Microfinance Institutions in India what drives their valuation" Prajnan Vol. XL No.1 2011 pp. 7 – 35.
[11]. Frances Sinha "State of microfinance in India 2009" Prepared for Institute of Microfinance as a part of project on state of microfinance in SAARC countries 2009.
[12]. India Top 50 MFIs: A financial awareness initiative of CRISIL CRISIL Ratings October 2009.
[13]. Jivan Kumar Chowdhury "Microfinance revolution and microfinance services in Indian perspective" Banking Finance Vol. XXI No.6 June 2008 pp. 5-8.
[14]. K.MuralidharaRao "MFIs in India: An overview" NABARD 2011 pp.57-66.
[15]. India Ratings and Research. (2015). Microfinance: Strong Comeback
[16]. Microfinance industry in India Lok Capital March 2010.
[17]. PadmajaManoharan RameshwariRamachandran Nirmala Devi "Microfinance institutions in India.